आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 08.05.2023 से 13.05.2023)

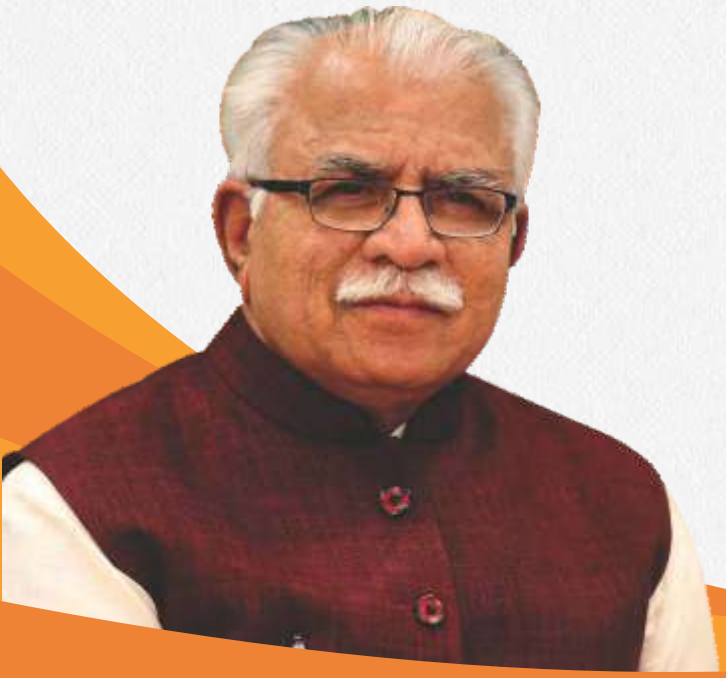

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 09.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण मसौदों/निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की गई। जोकि निम्नप्रकार से हैं–

6 नए उपमंडल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उप–तहसीलों, तहसीलों, उप–मंडलों और जिलों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक स्तर पर तालमेल लाना व सेवाओं का बेहतर वितरण है।

मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व में तय की गई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण के मापदंड के आधार पर और अन्य कारकों जैसे यातायात, परिवहन, सामाजिक

साप्ताहिक सूचना पत्र

समरूपता, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और भविष्य के विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए समिति ने 6 नए उपमंडल नामतः मानेसर (गुरुग्राम), नीलोखेड़ी (करनाल), इसराना (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़), और जुलाना (जींद) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को नगर निगम रोहतक की भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा एक पंजीकृत संस्था है और 100 से अधिक वर्षों से सक्रिय रूप से शिक्षण संस्थान चला रही है। वर्तमान में सभा द्वारा रोहतक में एक डिग्री कॉलेज, एक बी. एड. कॉलेज और एक स्कूल चलाया जा रहा है। सभा द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार के लिए किया जाएगा। कब्जा सौंपने से पहले सभा को विस्तृत नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए नगर निगम, रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच एक

समझौता किया जाएगा।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन के अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान।

इन अध्यादेशों को हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, प्रत्येक नगर पालिका में पिछड़े वर्ग 'ए' के लिए सीटें आरक्षित होंगी और आरक्षित सीटों की संख्या यथासम्भव रहेगी। नगर पालिका में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में उस नगर पालिका की कुल आबादी के लिए पिछड़े वर्ग 'ए' जनसंख्या के अनुपात का 0.5 या अधिक होने की स्थिति में अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाता है।

अनुसूचित जाति के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को छोडक़र पिछड़े वर्ग 'ए' की सबसे अधिक प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े वर्ग 'ए' के आरक्षण के लिए प्रस्तावित सीटों की संख्या के अधिकतम तीन गुना सीटों में से ऐसी सीटों को ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में भी बारी–बारी से आवंटित की जाएंगी। मंत्रिपरिषद ने 8 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग–ए को नगर पालिकाओं के चुनाव लडऩे में

साप्ताहिक सूचना पत्र

आरक्षण के अनुपात के प्रावधान के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

चूंकि, राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द से जल्द होने हैं इसलिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों और नगर परिषदों/समितियों के चुनावों में पिछड़ा वर्ग–ए को आरक्षण के प्रावधान के लिए, अधिनियम, 1994 की धारा 6 और धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में प्रावधान करने के लिए अध्यादेश लाने की आवश्यकता है।

आबकारी नीति– 2023–24 को दी मंजूरी।

पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करना है। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए के लक्षित संग्रह के साथ खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है। इस राशि का

उपयोग पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए किया जाएगा। नई नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिला स्तर पर आईएफएल (बीआईओ) के लेबल का भी नवीनीकरण किया जाएगा।

साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छोटी (क्राफ्ट) ब्रेवरीज की लाइसेंस फीस कम की गई है। राज्य में वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए वाइनरी की सुपरवाइजरी फीस में कमी की गई है। नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को क्रमशः 2022–23 में 2600 से घटाकर 2500 तथा 2023–24 में 2500 से 2400 कर दिया गया है।

माइल्ड कैटेगरी के तहत एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। इसके अलावा, पब कैटेगरी (एल–10ई) यानी केवल बीयर और वाइन के उपभोग के लिए लाइसेंस शुल्क को और कम कर दिया गया है। थोक लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माने के प्रावधान कड़े किए गए हैं और लाइसेंसधारक द्वारा सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शराब प्रचार के विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आबकारी लाइसेंस के तहत शराब परोसने वाले सभी होटलों, पब और बार, रेस्तरां और कैफे के बाहर सावधानी बोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में फंसे हरियाणा के विद्यार्थी सकुशल घर लौटे

(दिनांक 09.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मणिपुर में पढ़ाई करने गए प्रदेश के विद्यार्थियों का सकुशल अपने घर लौटना शुरू हो गया है। सोमवार देर रात 5 विद्यार्थियों का पहला बैच दिल्ली पहुंचा। इन विद्यार्थियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही सकुशल घर वापसी के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया। विद्यार्थी बोले, थैंक यू हरियाणा सरकार, सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए। इन विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान से लेकर हवाई जहाज़ में बैठने और दिल्ली में उतरने तक सरकार निरंतर सम्पर्क साधे रहती है। हरियाणा भवन में विद्यार्थियों खाने व ठहराने की व्यवस्था भी की हुई है।

इन विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें मणिपुर से हरियाणा वापस लाने के समस्त प्रबंध हरियाणा सरकार ने किए थे, यहां तक कि उनकी हवाई जहाज की टिकट का इंतजाम भी हरियाणा सरकार ने किया है। इन प्रबंधों के लिए विद्यार्थियों ने हरियाणा सरकार विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताया है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार से उन्हें सकुशल वहां से निकालने की अपील की थी, जिसके बाद सरकार ने प्रो–एक्टिव होकर काम किया और लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा। हरियाणा सरकार सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी लगातार संपर्क में है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 16 विद्यार्थी मणिपुर में विभिन्न संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनमें से सभी विद्यार्थी सकुशल घर पहुंच चुके है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन विद्यार्थियों और इनके परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जन संवाद पोर्टल का लोकार्पण

(दिनांक 10.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सीएम ग्रीवेंसिंज रिडरेशल एण्ड मोनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का लोकापर्ण किया। इस पोर्टल पर जन संवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं एवं सुझावों को अपलोड कर पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा।

इसके बाद संबंधित अधिकारी इन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ता के पास समस्या बारे संदेश भी जाएगा। उन्होंने कहा कि राईट टू सर्विस एक्ट के तहत 600 से अधिक सेवाएं आती हैं। इनके अलावा आने वाली सभी समस्याओं को अधिकारी समयबद्ध ढंग से निदान सुनिश्चित करेंगें।

उन्होंने कहा कि जनता के साथ संवाद करते समय सरकार के समक्ष आने वाली सभी समस्यांओं को कार्यान्वित करने के लिए जिला एवं मुख्यालय स्तर पर इन समस्याओं को पोर्टल पर

अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का निदान के लिए शहरी स्तर पर नगर दर्शन पोर्टल एवं गांव स्तर पर ग्राम दर्शन पोर्टल बनाए गए है।

इन पर नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याओं एवं विकास कार्य करवाने के लिए भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वह शिकायत अधिकारी के पास स्वतः ही चली जाएगी और वे उन पर संज्ञान लेकर एस्टीमेट एवं बजट आदि का प्रावधान कर पूरा करने का कार्य करेंगे। इन पोर्टल पर आने वाली समस्याओं को प्रतिनिधियों के माध्यम से

सहमति प्रदान की जाती थी, लेकिन अब नागरिक सीधे ही इन समस्याओं को पोर्टल पर भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिस पर जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक इस पोर्टल पर 3609 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की गई है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते से शिष्टाचार भेंट

(दिनांक 10.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास संत कबीर कुटीर पर केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिष्टाचार भेंट की।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर विचार विमर्श किया।

इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही परिवार पहचान पत्र योजना के बारे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हाई पॉवर परचेज कमेटी व हाई पावर वर्क्स कमेटी की बैठक

(दिनांक 10.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 275 करोड़ रुपये की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई।

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बैठक में सिंचाई, पुलिस, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कुल 26 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 18 एजेंडे को मंजूरी दी गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उन्होंने बताया कि आज विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 7 करोड़ 7 लाख रुपये की बचत की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बैठक में पशु बीमा के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रेट कॉन्ट्रेक्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही पशु बीमा योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को 70 करोड़ रुपये का क्लेम दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने हेतू व्यस्थाओं को सुव्यवस्थित किया है।

पहले केवल एल–1 पार्टी से ही नेगोशिएशन किया जाता था। हमने यह सिस्टम बनाया है कि बोली राशि के 5 प्रतिशत तक की रेंज में एल–5 तक पार्टियों को नेगोशिएशन के लिए बुलाया जाता है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से रेट तय किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय यही है कि जनता का 1–1 रुपये पारदर्शी तरीके से जनता के हित के लिए ही खर्च हो।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नूहं में साइबर फ्रॉड पर हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन

(दिनांक 10.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा जिला नूंह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ की गई रेड के बाद जांच में अब तक देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। ये महाठग फर्जी सिम, आधार कार्ड इत्यादि द्वारा देशभर के लोगों से ठगी करते और फर्जी बनाए बैंक खातों में राशि डलवा देते ताकि पुलिस इन तक ना पहुंच सके। इल जालसाजों द्वारा हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली और यूपी से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। इनके पकड़े जाने से देशभर में साइबर ठगी के लगभग 28,000 केस ट्रेस हुए हैं।

नूंह पुलिस अधीक्षक श्री वरूण सिंगला ने आज नूंह में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 27/28 अप्रैल की मध्यरात्रि को 5000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने जिले के 14 गांवों में एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 125 संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें

गिरफ्तार किया गया। सभी को अदालत में पेशकर 7 से 11 दिन की रिमांड पर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इन साइबर अपराधियों से पूछताछ के लिए पूरे हरियाणा से 40 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की। इस प्रकार साइबर विशेषज्ञों की मदद से पकड़े गए साइबर अपराधियों से निरंतर पूछताछ की गई और साइबर धोखाधड़ी द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के साथ–साथ फर्जी सिम और बैंक खातों के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

साइबर जालसाजों के ठगी करने के तरीके का विवरण देते हुए श्री वरुण सिंगला ने बताया कि ये महाठग फेसबुक बाजार/ओएलएक्स आदि पर बाइक, कार, मोबाइल फोन इत्यादि जैसे उत्पादों पर आकर्षक ऑफर का लालच देकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते थे। पीड़ित दिए गए मोबाइल नंबर पर जालसाज को कॉल करता और जालसाज कूरियर शुल्क, उत्पाद के परिवहन आदि के बहाने पीड़ित को धोखा देता लेकिन उत्पाद कभी डिलीवर नहीं होता था। ये जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्य रूप से नटराज पेंसिल की पैकेजिंग से संबंधित वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन पोस्ट करते थे, प्रति माह 30,000 रुपये की कमाई का वादा करते थे और पंजीकरण शुल्क, पैकिंग सामग्री, कूरियर शुल्क आदि के बहाने भोले–भाले लोगों को ठगते थे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल, यमुनानगर का उद्घाटन

(दिनांक 11.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिला यमुनानगर में 275 बिस्तरों वाले मुकन्द लाल जिला नागरिक अस्पताल सहित 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन संस्थापनों पर लगभग 232 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पोम्प रोग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) व स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) इत्यादि 55 दुर्लभ बिमारियों से ग्रसित मरीजों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन मरीजों को 2750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अभी

तक सरकार की ओर से थैलेसिमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज–3 एवं 4 के मरीजों को पेंशन प्रदान की जाती है। आज से 55 दुर्लभ बिमारियों को भी इस सूची में जोड़ दिया गया है और इस आर्थिक सहायता हेतू सरकार ने 25 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में थैलेसिमिया व हीमोफीलिया बिमारी से ग्रसित 3 हजार मरीज, कैंसर स्टेज–3 एवं 4 के 4 हजार मरीज और 55 दुर्लभ बिमारियों के लगभग 1 हजार मरीज हैं, जिन्हें सरकार की ओर से पेंशन स्वरूप आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 55 दुर्लभ बिमारियों की सूची स्वास्थ्य् विभाग की वेबसाइट पर चिन्हित करवा दी हैं, इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति वेबसाइट पर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन करें।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यव सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हर वर्ष स्वास्थ्यव क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, जिसके तहत गरीब व जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्यन बीमा की सुविधा मिली। इसमें प्रदेश के साढ़े 15 लाख परिवारों को लाभ मिला है।

लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाकर इस योजना का दायरा बढ़ाया और चिरायु हरियाणा योजना लागू की। आज प्रदेश के लगभग साढ़े 29 लाख परिवारों को इन योजनाओं के तहत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक स्वस्थि हो, इसके लिए गांवों में आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स खोले जा रहे हैं। योग के लिए 1000 योग शिक्षक लगाए गए हैं। इसके अलावा, सही खान–पान की जानकारी के लिए डायटीशियन्स की नियुक्तियां की जाएंगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सिरसा जिले का 3 दिवसीय दौरा

(दिनांक 12.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रामीण अंचल में नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने के लिए शुरू किए गया जन संवाद कार्यक्रम का पढ़ाव अब सिरसा जिले में पहुंच चुका है। 13 मई से 15 मई तक 3 दिवसीय सिरसा दौरे के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 9 गांवों में जन संवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस दौरान विभिन्न बड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन व शिलान्यास कर जिलावासियों को मनोहर सौगात देंगे।

सिरसा के गांव खैरेकां में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला सिरसा के गांव खैरेकां में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों में स्थित तालाबों की सफाई करवा कर उनकी गाद बाहर निकालें, जो गाद तालाबों से

निकलेगी, किसान उस गाद को अपने खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में 18 हजार तालाब हैं, इन तालाबों की सफाई पंचायतें अपने स्तर पर करवा सकती हैं। गाद निकलने के बाद किसान इस गाद को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ग्राम पंचायत से ले सकते हैं। गांवों में सफाई व्यवस्था पंचायतें अपने स्तर पर देखें और इसमें ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि गांव खैरेकां में सवा दो करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे वॉटर वर्क्स के काम में तेजी लाकर इसे जल्द पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा गांव के खेतों में सिंचाई के लिए अबूदगढ डिस्ट्रीब्यूटरी व सुखचौन डिस्ट्रीब्यूटरी पर रिमॉडलिंग का काम करवाया गया है, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि गांव खैरेकां का भूमि जल स्तर गिर रहा है, इसलिए किसान पानी की बचत करें और सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

को अपना कर खेती करें। किसान बरसात के समय में अपने बोरवेल के माध्यम से पानी को रिचार्ज भी कर सकते हैं।

सिरसा के गांव बड़ागुढ़ा में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा जिले के गांव बड़ागुढ़ा में जन संवाद कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी से ईलाज के पैसे लेने के एक मामले में सीएमओ को सख़्त निर्देश दिए कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज शाम तक लाभार्थी को उसकी 20 हजार रुपये की राशि वापिस मिल जानी चाहिए।

जन संवाद कार्यक्रम में गांव बड़ागुढ़ा के एक युवक ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन निजी अस्पताल ने उनसे ईलाज के नाम पर 20 हजार रुपये लिए।

इसी प्रकार, एक अन्य युवक से निजी अस्पताल द्वारा ईलाज के नाम पर पैसे

लेने के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच कर समुचित कार्यवाही की रिर्पोट 7 दिन में सौंपें। इसके अलावा, यदि कोई और मामला इस प्रकार का सामने आता है तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए।

जन संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गांव के युवक ने समस्या बताते हुए कहा कि जमीन संबंधी कार्य करने की एवज में गांव छतरियाँ के नहरी पटवारी नरेश ने उनसे 5 हजार रुपये मांगे। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नहरी पटवारी नरेश सस्पेंड करने के आदेश दिए।

कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करना।

कालांवाली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 47 करोड़ 61 लाख 23 हजार रुपये से अधिक की 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 32 लाख 58 हजार रुपये की एक परियोजना का उद्घाटन व 47 करोड़ 28 लाख 65 हजार रुपये की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कालांवाली के अंबेडकर भवन में 4 करोड़ 59 लाख 92 लाख रुपये की लागत से बीएमबी आरडी 322625 पर पुनरू बनने वाले सिंगल स्पेन स्टील ब्रीज के कार्य, एक करोड़ 50 लाख 30 हजार रुपये की लागत से गांव देसू मलकाना से ग्याना पंजाब तक बनने वाली लिंक रोड़ के कार्य व 25 करोड़ रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग के विभिन्न 28 विशेष मरम्मत के कार्य का शिलान्यास किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

डॉयल–112 सेवा का उपयोग करने वाले नागरिकों से सीधा संवाद

(दिनांक 13.05.2023)

प्रभाव : य मुख्यमंत्री जी ने आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष चर्चा कार्यक्रम में डॉयल–112 सेवा के तहत आपातकालीन समय में सहायता प्राप्त करने वाले नागरिकों से सीधा संवाद कर कहा कि नागरिकों को आपातकालीन समय में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए शुरू की गई डायल–112 सेवा बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। जिस प्रकार डायल–112 सेवा मुसीबत के समय नागरिकों को सहायता प्रदान कर रही है, उसी तरह आगे भी यह प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

नागरिकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डायल 112 सेवा बहुत ही अच्छी है और आवश्यकता पड़ने पर जब भी उन्होंने इस सेवा का उपयोग किया है, तो डायल–112 की गाड़ी महज 8 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई थी। संवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि डायल–112 सेवा पर कॉल किया था, उस समय पुलिस कर्मियों ने व्यवहार अच्छा नहीं किया। इस पर सख्त संज्ञान लेते हुऐ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने

कहा कि यह विशेष चर्चा इस उद्देश्य से की जा रही है ताकि सुखद अनुभवों के साथ यदि किसी नागरिक के साथ कुछ बुरा अनुभव हुआ है तो उसकी जानकारी लेकर ऐसे संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर सभी व्यवस्थाओं को ठीक करना है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के नागरिकों को संकट के समय तुरंत मदद प्रदान करने के उद्देश्य से 12 जुलाई 2021 को डायल–112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली का शुभारम्भ किया था। उन्होंने कहा कि पहले विभिन्न प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के अलग–अलग नम्बर होते थे। यही नहीं विभिन्न प्रदेशों में एक ही सेवा के नम्बर भिन्न होते थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक देश एक आपातकालीन नम्बर–112 लांच किया गया। अब इसकी सहायता से देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कहीं से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब कोई अपराध या दुर्घटना होती थी तो लोगों को शिकायत रहती थी कि मदद समय पर नहीं पहुंचती। लोगों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए ही यह प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के शुरू होने से संकट के समय सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता आई है और विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2021 से अब तक स्टेट इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर में 1 करोड़ से भी अधिक कॉल आई हैं । इनमें से 15 लाख 13 हजार कॉल पर आपातकालीन सेवाओं के लिए तुरंत वाहन भेजे गए।